नवभारत 20 जुलाई 2025

रविवारीय

ब्रह्मदीप अलूने

ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली वायु रक्षा प्रणाली में सेंध लगाकर दुनिया की महाशक्तियों को सुरक्षा संकट का बखूबी अहसास करा दिया है. इजराइल की रक्षा प्रणाली के कमजोर पड़ने से अमेरिका जैसे देशों की चिंता भी बढ़ गई है.

युद्ध के मोर्चे और सुरक्षा कवच की फिक्र

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य एवं परमाणु शक्ति संपन्न देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस भी आज विश्वासपूर्वक यह दावा नहीं कर सकते कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली अभेद्य है. ईरान और इजराइल के बीच हालिया युद्ध के नतीजों ने इस तरह के दावों की नींव हिला दी है. ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली वायु रक्षा प्रणाली में सेंध लगाकर दुनिया की महाशक्तियों को सुरक्षा संकट का बखूबी अहसास करा दिया है. इजराइल की रक्षा प्रणाली के कमजोर पड़ने से अमेरिका जैसे देशों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने भी थाड प्रणाली और इजराइल द्वारा अमेरिकी कंपनी बोइंग की मदद से विकसित किए गए एरो-3 को भी इस युद्ध में कड़ी परीक्षा हुई थी.

अमेरिका और इजराइल गहरे रणनीतिक साझेदार हैं. अमेरिका की सैन्य क्षमता विश्व में सबसे व्यापक और तकनीकी रूप से उन्नत मानी जाती है. ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों और रिहाइशी इलाकों पर हमला करके अमेरिकी सुरक्षा को भी चुनौती दी है. कतर के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले के सैन्य संदेश स्पष्ट हैं. वहीं, उत्तर कोरिया की आक्रामकता से अमेरिका पहले से ही चिंतित है. अत्याधुनिक हथियारों की होड़ के बीते सौ साल में आक्रामकता के साथ नियंत्रण और संतुलन की कूटनीति को कई बार देखा और परखा गया. वर्ष 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट अमेरिकी और सोवियत नेतृत्व के बीच शीत युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़ था और विश्व परमाणु युद्ध की कगार पर खड़ा था. हालांकि, समय रहते अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच इस संकट को सुलझा लिया गया और इससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा टल गया. लेकिन बहुध्रुवीय दुनिया को आकार देने के लिए कई देश अपने सुरक्षा कवच को मजबूत करने एवं सैन्य क्षमता को बढ़ाने को लेकर अरबों डालर खर्च कर रहे हैं.

अमेरिका, इजराइल, रूस, चीन, यूरोप और भारत जैसी सैन्य शक्तियां अपनी सुरक्षा के लिए वायु रक्षा प्रणाली पर निर्भर हैं. अमेरिका के पास मौजूद थाड यानी टर्मिनल हाइ एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम% को उसने कई सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए तैनात किया है. यह प्रणाली मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम है. अमेरिका की पैट्रियट प्रणाली क्रूज मिसाइलों और सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करती है. एस-300 और एस-400 रूस की एक लंबी दूरी की मिसाइल रोधी प्रणाली है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों, विमानों और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है. चीन की एच क्यू-9 रक्षा प्रणाली रूसी एस-300 से प्रेरित है, जो बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों सहित कई तरह के खतरों को रोक सकती है. वायु रक्षा प्रणाली एस-400 को भारतीय सेना ने सुदर्शन चक्र नाम दिया है. इसे मौजूदा समय में दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणाली कहा जा सकता है. आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हवाई हमलों से भारत का बचाव कर इसने अपनी श्रेष्ठता भी दिखाई है.

वहीं, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में दुनिया की बेहतरीन वायु सुरक्षा प्रणाली की परीक्षा हुई. इजराइल में आयरन डोम मिसाइल रोधी प्रणाली रडार के जरिए मिसाइलों और रोकेटों की पहचान व निगरानी करती है. इस सुरक्षा कवच ने हिजबुल्ला, हुती और हमास के मिसाइल और ड्रोन हमलों से कई बार बखूबी बचाव कर अपनी उपयोगिता को साबित किया है. लेकिन ईरान की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों ने आयरन डोम को भेद कर कई महत्वपूर्ण इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के एक डिजाइन को चुना है, जो उनके मुताबिक भविष्य की मिसाइल रक्षा प्रणाली होगी. ट्रंप का कहना है कि इसका लक्ष्य अमेरिका को अगली पीढ़ी के हवाई खतरों से लड़ने में सक्षम बनाना है. अमेरिका अपनी गोल्डन डोम रक्षा प्रणाली पर एक सौ पचहत्तर अरब डालर का खर्च कर रहा है. इस प्रणाली के तहत अंतरिक्ष में ऐसे सेंसर और इंटरसेप्टर होंगे, जो हवाई हमलों के खतरों को रोक सकेंगे. इस समय दुनिया के सभी ताकतवर देशों की कोशिश है कि वे हवाई हमलों के प्रति बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था करें.

विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से किए जाने वाले हमलों से बचाव करने और उन्हें रोकने के लिए बनाया गया है. जबकि एरो-2 और एरो-3 को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है. इन सबके बीच तुर्किये की स्टील डोम बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली पर भी चर्चा हो रही है. यह प्रणाली नेटवर्क केंद्रित होगी और एआइ के जरिए तुर्किये के हवाई क्षेत्र की रक्षा करेगी. दावा किया जा रहा है कि स्टील डोम में चार परतें होंगी, जो बहुत कम दूरी, कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी के खतरे से निपटेंगी. हालांकि, युद्ध के दौरान इसका परीक्षण कितना कारगर साबित होगा, इसका आकलन करना अभी मुश्किल है. वैसे दुनिया की सबसे बड़ी चिंता हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिससे बचने का अभी तक कोई सुरक्षा कवच नहीं बन पाया है. क्रूज मिसाइल धरती की सतह के नजदीक उड़कर कम दूरी तक मार करती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल वायु मंडल से बाहर जाकर हजारों किलोमीटर दूर तक निशाना भेद सकती है. बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाने के लिए अमेरिका और रूस ने अंतरिक्ष में इंफ्रारेड सेंसर वाली उपग्रह प्रणाली विकसित की है. मगर, हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ पाना आसान नहीं है. दावा किया जा रहा है कि चीन ने वर्ष 2021 में दो संभावित हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया था, जिनमें एक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है.

इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2019 में यह घोषणा कर दुनिया को अचंभित कर दिया था कि रूस की एवनगार्द हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली मौजूदा और भविष्य में आने वाली किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली को मात दे सकती है.

> दूसरी ओर अपनी वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई देश भारी निवेश कर रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के एक डिजाइन को चुना है, जो उनके मुताबिक भविष्य की मिसाइल रक्षा प्रणाली होगी. ट्रंप का कहना है कि इसका लक्ष्य अमेरिका को अगली पीढ़ी के हवाई खतरों से लड़ने में सक्षम बनाना है. अमेरिका अपनी गोल्डन डोम रक्षा प्रणाली पर एक सौ पचहत्तर अरब डालर का खर्च कर रहा है. इस प्रणाली के तहत अंतरिक्ष में ऐसे सेंसर और इंटरसेप्टर होंगे, जो हवाई हमलों के खतरों को रोक सकेंगे. इस समय दुनिया के सभी ताकतवर देशों की कोशिश है कि वे हवाई हमलों के प्रति बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था करें. इस वर्ष मई में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक सौ बयालीस बिलियन डालर का रक्षा सौदा किया है, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा हथियार सौदा करार दिया गया है. जापान, आस्ट्रेलिया, तुर्किये और दक्षिण कोरिया जैसे कई देश अब मिसाइल रक्षा प्रणालियों में भारी निवेश कर रहे हैं. कतर और संयुक्त अरब अमीरात भी इस दौड़ में शामिल है. भविष्य में और भी कई देशों की सेनाएं मिसाइल रक्षा प्रणाली में निवेश करना चाहेंगी. लेकिन इससे गरीब, पिछड़े और विकासशील देशों में विकास कार्य अवरुद्ध होंगे. मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाने में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ के कारण विध्वंसक हथियारों का निर्माण और ज्यादा बढ़ेगा. अंततः यह स्थिति मानव अस्तित्व के लिए भी एक बड़ा संकट खड़ा कर सकती है.

व्यंग्य

इज्जत वाली चाय...!

रवि उपाध्याय
लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

पूरे देश और दुनिया में यदि सम्मान का प्रतीक कोई पेय है तो वह चाय ही है. गरीब हो या अमीर उसकी यही पहली पसंद है. जहाँ भी अतिथि के प्रति थोड़ी सी भी चाह होगी वहां चाय जरूर होगी. चाय आगंतुक अतिथि के लिए सम्मान और इज्जत का प्रतीक है. चाय से उस समय इज्जत में तब चार चांद लग जाते हैं, जब चाय मुफ्त की हो. अपनी जेब से पैसे खर्च कर चाय पीना भी भला कोई इज्जत की बात है ? मुफ्त की चाय मिलना यह साबित करता है कि व्यक्ति कितना इज्जतदार है. गोस्वामी तुलसीदास जी की शैली में इस पर एक दोहा मुफीद बैठेगा –कि देखत ही मुस्काए नहीं और नजरें रहो चुराए, तुलसी तहां न जाइयो नहीं मिलेगी चाय.

जब अंग्रेज हमारे देश में व्यापारी बन कर आए थे तो वह अपने साथ चाय लेकर आए थे. चाय अंग्रेज अफसरों की टेबल की शान हुआ करती थी. अंग्रेजों के आने के बाद से चाय एक स्टेटस सिंबल बन गई. इसे इज्जत का प्रतीक माना जाने लगा. हमारे नेता और जनता अंग्रेजों से बहुत प्रभावित रही है. इसी के चलते सभी चाय के मुरीद हो गए. तभी तो गांधी जी ,नेहरू जी ने भी अंग्रेजों के साथ चाय पीकर देश को आजादी दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया है. आजादी के बाद गरीब हो या अमीर सबके लिविंग स्टैंडर्ड में ऐसा उछाल आया कि सबके घर में बिहाने बिहाने चाय उबलने लगी. आजादी के पहले जिस चाय पर अंग्रेज बहादुर के बाद अमीर रायबहादुरों का कॉपीराइट था वह आज़ादी के बाद पूरे समाज और देश का हो गया. यह चाय का ही प्रताप है कि रेल के डब्बे में चाय बेचने वाला एक साधारण सा शख्स देश का प्रधानमंत्री बन गया और जो सोने के चम्मच के साथ इस पुण्य धरा पर आए, वो चम्मच ही हिलाते रह गए.

पहले अमीर लोग चाय पान करते थे. लेकिन देश की आजादी के बाद गरीबों के लिए चाय भी उसी तरह आम हो गई जैसे आज नेता. आज गली – गली में चाय के ठेले भी मिल जाएंगे और वहीं गली–गली में नेता भी मिल जाते हैं. जो अपनी स्वामिभक्ति का सरे बाजार मुजाहिरा करते हुए अपनी गरदनों में बड़े गर्व से इक रंगे, दुरंगे, तिरंगे नीले पीले, लाल गुलाबी पटके धारण किए रहते हैं . यह पटके एक तरह से जायज, नाजायज गैर कानूनी काम करने के लायसेंस जैसे होते हैं. इससे पता चल जाता है कि कौन किस नेता या पार्टी के खूंटे से पोषित और पल्लवित है. इन पटकों की तुलना महिलाओं द्वारा मांग में भरे सिंदूर से की जा सकती है.

अब बात चाय की तो आज हालात यह है कि आप किसी के यहां जाओ और वहां चाय ऑफर नहीं की जाए तो यह अशिष्टता मानी जाती है. साफ शब्दों में कहा जाए तो यह इज्जत और सम्मान का पर्याय बन गई है. चाय और इज्जत वैसे ही एक दूसरे के पूरक हैं जैसे कप और प्लेट की जोड़ी.

जिस पात्र में चाय पेश की जाती है उससे अतिथि का वज़न का अंदाज लगाया जा सकता है. किसी बड़े और मझोले अधिकारी को जब चाय परोसी जाती है तो चाय की टेबल पर टिकोजी का कोट पहने चाय के उबले हुए पानी से भरी केटली, उसके साथ रिद्धि सिद्धि की तरह मौजूद मिल्क और शुगर पॉट और स्टील की चमचमाती चम्मच अवश्य होती है. जैसे जैसे व्यक्ति का स्तर घटता जाता है वैसे चाय का पात्र भी कप –प्लेट, मग्गे और कांच के गिलास का सफर तय करते हुए कागज के छुटके और ढक्कननुमा गिलास तक जा पहुंचती है.

आज चाय का सफर कप– प्लेट, सिंगल, कट और गिलास से होता हुआ कागज के ढक्कन नुमा गिलास तक आ पहुंचा. जैसे जैसे हमारे दिल छोटे होते गए वैसे ही चाय की दुकानों में मिलने वाले चाय के पात्र का आकार उसी तरह सिकुड़ता गया जैसे अंग्रेजों के जाने के साथ हमारे देश की सीमाओं का आकार घटता गया. आजादी आने के बाद चाय का यह गुण और पता चला कि इसके पान से नेताओं में दान शीलता की भावना आती है. यही कारण है कि हमने सिया चीन की जमीन, गिलगिट बाल्टिस्तान और दक्षिण समुद्र में द्वीप पड़ोसियों को दान कर दिया. यह चाय ही है जिसने तबला वादक स्व.जाकिर हुसैन को वाह ताज वाले जुमले के साथ गली–गली में लोकप्रिय बना दिया. इसके पहले कम लोग ही उनके बारे में जानते रहे होंगे .

एक बात और चाय– पान रिश्वत लेने और देने का एक सभ्य तरीका बन गया. सरकारी विभागों में चाय–पान रिश्वत या सेवा शुल्क का कोड वर्ड बन गया. यह इज्जत और इजाजत दोनों का मौन भाव बन गया. खुद खरीद कर चाय पीना खरीदने वाले की तलब का द्योतक है,और किसी के द्वारा मनुहार के साथ चाय पीने का ऑफर, इज्जत वाली चाय है. चाय वह अमृत है जो फेविकोल की तरह नए रिश्तों को मजबूत करने की गारंटी है. तभी तो बेटी नए जीवन की शुरुआत करने वाली होती है तो वह अपने संभावित ससुराल वालों के समक्ष चाय की ही ट्रे लेकर जाती है. इस मौके पर एक घटना याद आती है.हमारे एक परिचित कमल किशोर जी एक कस्बे में नायाब तहसीलदार बन कर पहुंचे . अकेले थे . एक पटवारी सेवा में रहता था. एक सुबह साहब ने फरमाइश की – लाला जी आज तो इज्जत वाली चाय पीनी है. लाला जी मुस्कराए . अब वे दोनों एक साइकिल रिक्शा पर लद गए और इज्जत की चाय की तलाश में कस्बा भ्रमण को निकल पड़े . कस्बे में दो ही लोगों का रुतबा होता है या तो हेठ साहब का या लाला जी का.

दोनों कस्बा में एक घंटा तक घूमते रहे . जो भी पटवारी को देखता खट से अपने दरवाजे बंद कर लेता. नायब तहसीलदार ने पटवारी से कहा,पटवारी जी आप की तो यहां बड़ी इज्जत है भाई, जो भी तुम्हें देखता है खटाक से दरवाजे बंद कर लेता है. मैं तो यहां नया नया हूं, भला मुझे यहाँ कौन जानता है. उसी समय एक व्यक्ति ने पटवारी जी को देखा तो – वह जोर से बोला अरे पटवारी जी सुबह –सुबह ? आइए चाय तो पी लीजिए . इतना सुनते ही दोनों यह बुदबुदाते हुए रिक्शे से कूद पड़े . मिल गई इज्जत वाली चाय. इस तरह उनका इज्जत की चाय पीने का अरमान पूरा हुआ. बाद में पता चला कि चाय पिलाने वाले व्यक्ति का कोई काम पटवारी जी के पास अटका था.

तो भाई साहब हर कोई इज्जत का तलबगार है. सरकारी बाबूओं को तो इज्जत की चाय की बड़ी चाह होती है. उनकी डिमांड केवल चाय अकेली नहीं होती. चाय के साथ वाए भी जुड़ी रहती है. उसमें सिगरेट या पान हिडन एजेंडे जैसा होता है.

डिजिटल समावेशन एवं जनजातीय विकास

डॉ. दिलीप सिंह

19 जुलाई 2025 भारत के जनजातीय समुदाय, जो ऐतिहासिक रूप से समतावादी सामाजिक संरचनाओं में रहते आए हैं, अक्सर जाति, वर्ग और लिंग भेद से रहित माने जाते रहे हैं. परंपरागत रूप से, कई जनजातियाँ प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर निर्वाह जीवनशैली अपनाती थीं, जिसमें शिकार, संग्रहण और झूम खेती शामिल थी. हालाँकि, बाहरी ताकतों—औपनिवेशिक प्रशासकों, बसने वालों, और बाद में औद्योगिक तथा विकास परियोजनाओं—के आगमन ने जनजातीय आबादी को संसाधन–समृद्ध क्षेत्रों से विस्थापित कर अधिक दूरस्थ और कम उपजाऊ क्षेत्रों में धकेल दिया.ब्रिटिश शासन के दौरान, कई जनजातीय–प्रभुत्व वाले क्षेत्रों को भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत बहिष्कृत या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था.

स्वतंत्रता के बाद, इन क्षेत्रों को भारतीय संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के माध्यम से विशेष संरक्षण में लाया गया, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए स्व–शासन और विशेष विकास योजनाओं का प्रावधान करती हैं.

> भारत में 97 .0 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, फिर भी 30त्न भारतीय नेटवर्क से बाहर यानी डिजिटल रूप से असंबद्ध हैं. कोविड–19 के दौरान हमने डिजिटल खाई की कीमत देखी. हमारे लाखों छात्र, विशेष रूप से जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के, अपनी स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए, क्योंकि उनके लिए पूर्ण तालाबंदी थी, जबकि बाकी लोग डिजिटल जुड़ाव के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे.भारत सरकार ने डिजिटल भारत निधि के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके सार्वभौमिक सार्थक कवरेज प्रदान करने की पहल की है. मध्य प्रदेश, जो 55,000 से अधिक गाँवों वाला मुख्य रूप से एक ग्रामीण राज्य है, में ग्रामीण क्षेत्रों में 96त्न कवरेज है, जिसका अर्थ है कि 2,000 से भी कम गाँव अछूते बचे हैं, और इन अछूते गाँवों में से 90 प्रतिशत से अधिक जनजातीय गाँव हैं. यदि हम टेली–घनत्व देखें, जो प्रति 100 लोगों पर दूरसंचार उपयोगकर्ताओं की संख्या है, तो अखिल भारतीय स्तर पर यह 85 .36त्न है, और मध्य प्रदेश का कुल टेली–घनत्व 69 .70त्न है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा सबसे कम टेली–घनत्व है (टी.आर.ए.आई., 2025). मध्य प्रदेश का ग्रामीण टेली–घनत्व केवल 42त्न है, जबकि ग्रामीण मध्य प्रदेश में मोबाइल कवरेज 96 प्रतिशत है. अब सवाल निवेश पर प्रतिफल, सामर्थ्य, उपयोगिता, सुरक्षा आदि के बारे में उठता है.डिजिटल समावेशन अकेले कुछ नहीं कर सकता, जब तक हम बिजली, आवास, शिक्षा और सड़क–रेल संपर्कता प्रदान नहीं करते. इसका अर्थ है कि विकास के अन्य आयाम डिजिटल संपर्कता की क्षमता का सही मायने में जीवन और आजीविका के एक सच्चे सशक्तिकरण के रूप में दोहन करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

इन प्रावधानों के बावजूद, स्वतंत्रता के बाद के विकास मॉडल ने बड़े पैमाने पर ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण अपनाया है, अक्सर जनजातीय समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की अनदेखी की गई. जनजातियों को सशक्त बनाने के बजाय, कई विकास पहलों ने उन्हें और अधिक हाशिए पर धकेल दिया है.

डिजिटल संपर्कता की पहलें– कितनी सार्थक?– हाल की विकास पहलें, जैसे पी.एम. जनमन योजना और धरती आभा, का उद्देश्य जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल जुड़ाव सहित बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है. ये डिजिटल जुड़ाव योजनाएँ सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (अब डिजिटल भारत निधि के नाम से जाना जाता है) के माध्यम से वित्तपोषित की जाती हैं. हालाँकि, इन योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है.पिछले दो दशकों में डिजिटल क्रांति ने मानव दक्षता में सुधार के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया है. आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की अपनी क्षमता के साथ, यह तकनीकी प्रगति एक अमूल्य संपत्ति बन गई है. मध्य प्रदेश जैसे अनूठे राज्य में, जो अपने भौगोलिक वन आवरण, जनजातीय आबादी और सामाजिक–सांस्कृतिक आयामों के लिए जाना जाता है, डिजिटल संपर्कता अवसरों की भरमार प्रदान करती है. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई.टी.यू.), संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी ने 2020–2030 के दशक को %कार्रवाई का दशक% घोषित किया है, जिसका जनादेश अपने सदस्य देशों को सार्थक जुड़ाव प्रदान करना और सभी विभाजनों—ग्रामीण–शहरी, लिंग, आय, उपयोग और कवरेज—को पाटना है, ताकि कोई भी पीछे न छूटे. इसके अतिरिक्त, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र ब्रॉडबैंड आयोग ने 2025 तक विकासशील देशों में ब्रॉडबैंड को किफायती बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सामर्थ्य को मासिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के दो प्रतिशत से कम मूल्य पर ब्रॉडबैंड पहुंच की उपलब्धता के रूप में परिभाषित किया गया है.

मध्य प्रदेश में डिजिटल खाई की जमीनी हकीकत– भारत में सबसे बड़ी जनजातीय आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहाँ राज्य की लगभग 22त्न जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है. लक्षित प्रयासों के बावजूद, यह राज्य महत्वपूर्ण मानव विकास सूचकांकों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा में पिछड़ा हुआ है. %राज्य प्रदर्शन रिपोर्ट% के अनुसार, मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में इन दोनों क्षेत्रों में सबसे खराब आंकड़े दर्ज किए गए हैं. ये कमियाँ डिजिटल समावेशन की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से सीमित करती हैं, क्योंकि डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए बुनियादी साक्षरता और स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता होती है.इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के जनजातीय–प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में ग्रामीण टेली–घनत्व 40% से कम है, भले ही इन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज लगभग 96% है.

नए भाजपा अध्यक्ष के सामने सतह पर चुनौती नहीं

श्याम यादव

हेमंत खंडेलवाल को आने वाले समय में कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो अनसोची होगी. उन्हें पार्टी के भीतर और पार्टी के साथ सरकार का सामंजस्य बैठाने की चुनौती से रूबरू होना पड़ेगा. यही उनकी सफलता की कसौटी होगी.

प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद पर हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति से भाजपा के कई दावेदार अचंभित हुए हों, ऐसा नहीं हुआ. भाजपा ने इस बार कोई चौंकाने वाला कदम नहीं उठाया. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की पसंद के अनुरूप ही हेमंत खंडेलवाल का चयन हुआ. लेकिन, इसमें हेमंत खंडेलवाल की राष्ट्रीय स्वयं सेवक की पृष्ठभूमि ज्यादा कारगर रही. कुल मिलाकर डॉ मोहन यादव की तरह ही आरएसएस ने अपने नर्सरी से निकले एक और पौधे को राजनीति में वृक्ष के रूप में स्थापित कर दिया.

चूंकि राज्य विधान सभा के चुनाव 2028 में होंगे और लोकसभा के 2029 में यानी भाजपा के अध्यक्ष के अपने कार्यकाल में हेमंत खंडेलवाल के सामने कोई बड़ी चुनावी चुनौती नहीं होगी. लेकिन, पार्टी में आंतरिक संगठन को एकजुट रखने के साथ पार्टी के आदिवासी वोट बैंक को संभाले रखने की चुनौती भी सामने होगी. इन वोट पर कांग्रेस की नजर अभी से है और वह इन्हें अपनी ओर खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ रही. छोटी छोटी घटनाओं को पूरे आदिवासी वर्ग को नाराज़गी बताकर सरकार को घेरने की कोशिश करती रहेगी.

पार्टी और सरकार से अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति जन जाति और मुस्लिम वर्ग की भी अपेक्षाएं होगी जो उनके सामने होंगी. इन सबके अलावा असल चुनौती तो भाजपा की ही होगी. विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ और बाद में कांग्रेस से कई बड़े–छोटे नेताओ ने भाजपा का दमन थामा था. इनमें से कुछ तो पार्टी में घुल–मिल गए, कई मंत्री पद पर भी है. लेकिन, कुछ तो अभी भी अलग–थलग हैं. कोई पद नहीं मिलने पर वे उलझन में हैं. भाजपाई भी असहज है, क्योंकि, वे इन्हें नेता के रूप में स्वीकार नहीं हैं. क्योंकि, इन नेताओं के भाजपा में आने से भाजपा के अनेक वर्षों से जुड़े नेताओ की दावेदारी खत्म होती दिखाई देने लगी. ऐसे में पुराने नेताओं को साथ लेकर चलना और कांग्रेस से आए नेताओं को भी जोड़कर रखना चुनौती होगी.

इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के समय निगम, मंडल और बोर्डों में की गई नियुक्ति को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भंग कर दिया था. अभी भी निगम, मंडल और बोर्डों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हैं. इन पदों पर नियुक्तियों में नेताओं को समायोजित करना भी चुनौती होगी. जिन नेताओं की दावेदारी विधानसभा में थी उन्हें टिकिट नहीं मिलने से वे भी इन पदों के लिए दावेदार होंगे.

> भाजपा को अपना नया अध्यक्ष मिल गया। इसके साथ ही प्रदेश की राजनीति में एक इलाके की दखलअंदाजी शुरू हो गई। कहने को तो आने वाले तीन साल तक भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को न तो विधानसभा चुनाव का सामना करना पड़ेगा और न लोकसभा चुनाव की कोई चिंता रहेगी। वे बेफिक्र होकर पार्टी को मजबूती प्रदान करते रहेंगे। इसका यह आशय यह नहीं लगाया जा सकता कि उनका तीन साल का कार्यकाल आसानी से कट जाएगा.

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)